

इंदौर के विकास को मिली नई रफ्तार : लोक परिवहन के क्षेत्र में इंदौर को मिली बड़ी सौगात

मेट्रो परियोजना परिवहन तंत्र को आधुनिक बनाने के साथ ही शहर के विकास को करेगी नई गति प्रदान : माह न

सच संवाददाता ॥ भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर में मेट्रो ट्रेन का विस्तार केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत है। आज मेट्रो का नया चरण शुरू हुआ है और आने वाले समय में इसके और चरण पूरे होंगे। मेट्रो के माध्यम से इंदौर को उज्जैन और पीथमपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य क्रमश: आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को इंदौर में मेट्रो ट्रेन के नये चरण के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेट्रो के पहले चरण को मिले सकारात्मक प्रतिसाद के बाद अब इसका विस्तार शहर के अंदरूनी क्षेत्रों तक हो रहा है। यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में मेट्रो इंदौर सहित पूरे मालवा क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को नयी दिशा देगी। इंदौर के मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2 हजार 850 करोड़ रुपये की लागत से सुपर कॉरिडोर-3 से मालवीय नगर तक मेट्रो



कॉरिडोर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने बटन दबाकर मेट्रो का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, विधायक गो लू शुक्ला, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, मधु वर्मा तथा सुश्री उषा ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के

सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले सामने आई आर्थिक विकास दर के आंकड़े देशवासियों का उत्साह और गौरव बढ़ाने वाले हैं। अमेरिका की विकास दर लगभग 2 प्रतिशत और चीन की 4 प्रतिशत के मुकाबले भारत की विकास दर 7.8 प्रतिशत रहना देश की मजबूत आर्थिक स्थिति की दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के बड़े देशों के सामने अपने हितों और अपनी शर्तों के साथ मजबूती से अपनी बात रख रहा है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते आत्मविश्वास और सामर्थ्य का परिचायक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि

इंदौर को मिली मेट्रो की सौगात के साथ ही इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन के लिए 18 हजार 500 करोड़ रुपये की मंजूरी भी क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह परियोजना इंदौर, मालवा और पूरे मध्यप्रदेश के विकास में नया इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि इस रेल परियोजना के पूर्ण होने के बाद इंदौर और मुंबई के बीच आवागमन के लिए गुजरात होकर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंदौर से मनमाड़ के माध्यम से महाराष्ट्र और मुंबई से सीधा संपर्क स्थापित होगा। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी इंदौर और उज्जैन के बीच संपर्क और अधिक सुगम होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि

आने वाले समय में गुना से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर और इंदौर से मनमाड़ तक बेहतर रेल कनेक्टिविटी विकसित होगी। इसके साथ ही इन्दौर मेट्रो के उज्जैन तक विस्तार का संकल्प भी लिया गया है। इससे उज्जैन और इंदौर सहित आसपास के पूरे महानगरीय क्षेत्र को एकजुट करने में मेट्रो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि माँ देवी अहिल्या की नगरी इंदौर विकास और विरासत दोनों क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मेट्रो का सफर गांधीनगर से मालवीय चौराहे तक आगे बढ़ रहा है। इस कॉरिडोर की लंबाई 17 किलोमीटर है और इसमें 16 स्टेशन शामिल हैं। यह परियोजना इंदौर के परिवहन तंत्र को आधुनिक और सशक्त बनाने के साथ ही शहर के विकास को नयी गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारियों और मेट्रो परियोजना से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इंदौर को लगातार मिल रहा विकास की सौगातों का सिलसिला इसी तरह आगे भी जारी रहेगा।

मेट्रो परियोजना परिवहन के साथ ही विकसित भारत के निर्माण का महत्त्वपूर्ण माध्यम : मनोहर लाल

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इंदौर में मेट्रो के नए 11 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का शुभारंभ शहर के विकास की दिशा में मील का पत्थर है। पहले मेट्रो का लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा आउटर क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन नए कॉरिडोर के जुड़ने से मेट्रो अब शहर के प्रमुख क्षेत्रों से भी जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि मेट्रो के विस्तार से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध परिवहन की सुविधा मिलेगी। इससे शहर में आवागमन सुगम होगा और लोगों के समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो शहरों के विकास के साथ उद्योग और व्यापार को गति देने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष-2014 में देश के केवल पांच शहरों में 245 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क संचालित था, जबकि आज 26 शहरों में लगभग एक हजार 170 किलोमीटर लम्बा मेट्रो का नेटवर्क होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्थिर नेतृत्व में मेट्रो के विस्तार की यह गति विश्व में अमृतपूर्व है और भारत शीघ्र ही मेट्रो नेटवर्क के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन सकता है। उन्होंने कहा कि मेट्रो केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण की आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर २, औद्योगिकीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास होने पर ही भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इंदौर मेट्रो के विस्तार से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और उज्जैन सहित महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ने की दिशा में भी नई संभावनाएं बनेंगी। इससे इंदौर के उद्योग, व्यापार, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को और गति मिलेगी तथा आसपास के क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधा प्राप्त होगी।

मेट्रो परियोजना का मूल उद्देश्य, पीथमपुर-महू से देवास-उज्जैन और आगे मक्सी तक विस्तार करना है : विजयवर्गीय

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर मेट्रो की योजना का मूल उद्देश्य शहर के भीतर आवागमन को सुगम करने के साथ ही इंदौर के विस्तार को गति देना और शहर को विकसित करना था। इसी मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिये मेट्रो परियोजना का विस्तार पीथमपुर, महू, देवास- मक्सी और उज्जैन तक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पहला चरण शहर में पूरा होने के बाद दूसरे चरण का काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी इसके लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद मेट्रो को पीथमपुर तक ले जाने की योजना है। आगे औद्योगिक क्षेत्रों से होते हुए उज्जैन, अवंतिकापुरी और मक्सी तक इसके विस्तार की परिकल्पना है। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि अगले 10 से 15 वर्षों तक इंदौर क्षेत्र में मेट्रो का काम लगातार चलता रहेगा। यह एक दीर्घकालिक योजना है, जिसके माध्यम से इंदौर और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो का उद्देश्य केवल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि शहर का विकेंद्रीकरण और तेज गति से समग्र विकास करना है। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में मेट्रो का एक बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है। शहर के नागरिकों की मांग और इंदौर की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख हिस्सों में मेट्रो को भूमिगत करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि एमजी रोड जैसी प्रमुख और सुंदर सड़कों पर मेट्रो के खम्भे लगने से शहर के सौंदर्य पर असर पड़ सकता था। इसलिए इसे भूमिगत करने के लिए प्रयास किए गए। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि भूमिगत मेट्रो परियोजना से बजट में कुछ वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन इससे इंदौर की सुंदरता और पहचान सुरक्षित रहेगी।

मध्यप्रदेश में शुरू होगी नई मोबिलिटी क्रांति

इंदौर में 11-12 सितंबर को यात्री परिवहन विजन समिट

सच संवाददाता ॥ भोपाल

मध्यप्रदेश में यात्री परिवहन की तस्वीर बदलने की तैयारी है। प्रदेश सरकार इंदौर में 11 और 12 सितंबर को यात्री परिवहन विजन समिट-2026 आयोजित करने जा रही है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली दो दिवसीय समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। समिट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पर रहेगा।



होगी। खास बात यह है कि सरकार पीपीपी मॉडल के जरिए यात्री बसों के संचालन को बढ़ावा देने की दिशा में भी रोडमैप तैयार करेगी। इससे निजी क्षेत्र को परिवहन व्यवस्था में बड़े स्तर पर भागीदारी का मौका मिलेगा। समिट में यात्री परिवहन से जुड़े कई आधुनिक क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इनमें इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन मोबिलिटी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डिजिटल टिकटिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट बस स्टॉप, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस और परिवहन वित्त जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के लिए मध्यप्रदेश में निवेश और साझेदारी के नए अवसर तलाशे जाएंगे।



समिट की एक खास बात सरकार और उद्योग जगत के बीच सीधे संवाद को माना जा रहा है। इसमें शामिल कंपनियों को प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ वन-टू-वन बैठक का अवसर भी मिलेगा। कंपनियां अपने तकनीकी समाधान और बिजनेस मॉडल प्रस्तुत कर सकेंगी। इसके जरिए पायलट प्रोजेक्ट, निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। यात्री परिवहन विजन समिट से प्रदेश के लिए मोबिलिटी विजन-2030 को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम होगा। इसमें पीपीपी मॉडल को गति देने, डिजिटल-फर्स्ट मोबिलिटी फेमवर्क तैयार करने, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और सरकार-उद्योग के बीच सहयोग मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। समिट में छह प्रमुख विषयों पर विशेष फोकस रहेगा। इनमें पीपीपी आधारित मोबिलिटी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वित्तीय स्थिरता, स्वच्छ मोबिलिटी, एकीकृत टिकटिंग और बेहतर यात्री अनुभव शामिल हैं।



भोपाल। विधायक भगवानदास सबनानी के जन्मदिन पर वरिष्ठ भ्राजपा कार्यकर्ता लीतेंद्र सिंह मारण ने अपने समर्थकों के साथ स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।

बारिश में बफर सफारी का क्रेज, हजारों पर्यटकों ने निहारा बांधवगढ़ का जंगल

उमरिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून के दौरान भले ही कोर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बंद रहती हैं। लेकिन बफर क्षेत्र में पर्यटकों को लगातार आकर्षित कर रहा है। जुलाई और अगस्त 2026 में धमोखर और पनपता बफर क्षेत्र में करीब 2400 पर्यटकों ने 500 से अधिक पर्यटन वाहनों से जंगल सफारी का आनंद लिया। बारिश के बीच वन्य जीवों को करीब से देखने के लिए पर्यटकों की रूचि ने पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों में भी उत्साह बढ़ाया है। पिछले वर्ष जुलाई अगस्त की तुलना करें तो इस बार बफर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में इसी अवधि के दौरान करीब 2000 पर्यटकों ने 438 वाहनों से सफारी की थी।

वैध परिवहन के दस्तावेज नहीं दे सकी फर्म कटनी कलेक्टर न्यायालय ने लगाया 27.44 करोड़ रुपए का जुर्माना

सच संवाददाता ॥ कटनी

मध्यप्रदेश के कटनी जिले में रेत के स्टॉक में भारी गड़बड़ी के मामले में कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा एक्शन लिया है। सैंड पोर्टल पर दर्ज रेत के स्टॉक और मौके पर मिली रेत में 1 लाख 46 हजार 362 घनमीटर का अंतर पाए जाने पर मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर 27 करोड़ 44 लाख 29 हजार 650 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर न्यायालय ने फर्म को निर्धारित राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। मामले में करीब तीन साल

तक चली कार्रवाई और सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की ओर से अभियोजन पक्ष और कंपनी के अधिवक्ता ने अपने-अपने दस्तावेज और तर्क प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कलेक्टर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। जिले के स्वीकृत रेत भंडारण स्थलों में दर्ज स्टॉक के भौतिक सत्यापन के दौरान विजयरावगढ़ तहसील के ग्राम पुरैनी स्थित मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉक की जांच की गई। जांच में सामने आया कि सैंड पोर्टल पर 1 लाख

46 हजार 462 घनमीटर रेत का स्टॉक दर्ज था, जबकि मौके पर करीब 100 घनमीटर रेत ही मिली। इस तरह पोर्टल और वास्तविक स्टॉक में 1 लाख 46 हजार 362 घनमीटर का अंतर सामने आया। कटनी के माइनिंग अधिकारी रत्नेश दीक्षित के मुताबिक, पूरे प्रकरण की जांच के आदेश 30 सितंबर 2023 को तत्कालीन खनिज अधिकारी को प्राप्त हुए थे। इसके बाद कलेक्टर के निर्देशन में 1 अक्टूबर 2023 को खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ग्राम पुरैनी स्थित रेत भंडारण स्थल पर पहुंची।

कौन है बिट्टू तबाही? जिसे डच सीईओ ने ऑफर की नौकरी नदी सफाई के जुनून से केविन पीटरसन भी हुए मुरीद

सच संवाददाता ॥ भोपाल/राजगढ़

अजनार नदी के किनारे रोज एक लड़का पहुंचता था। हाथ में कोई बड़ी मशीन नहीं, तेरना भी नहीं आता था, लेकिन नदी से कचरा निकालने का जुनून जरूर था। शुरुआत में लोगों ने इसे सनक समझा, किसी ने मजाक उड़ाया तो किसी ने इसे बेकार की कवायद बताया। मगर ब्यावरा का 21 वर्षीय बिट्टू अपने इरादे पर कायम रहा। दिन बीतते गए और नदी से निकलता कचरा बढ़ता गया। बिट्टू की मेहनत की तस्वीरें सोशल मीडिया तक पहुंचीं तो कहानी ब्यावरा से निकलकर देश-दुनिया तक जा पहुंची। उद्योगपति आनंद महिंद्रा और मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई लोगों ने उसके प्रयास की सराहना की। यहां तक कि नीदरलैंड की पर्यावरण संस्था ‘द ओशन क्लोनअप’ के सीईओ बोयान स्लाट ने भी उसकी मुहिम

से प्रभावित होकर उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दे दिया। बिट्टू ब्यावरा में रहते हैं और बीएससी सेकंड ईयर में बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना नाम ‘बिट्टू तबाही’ रखा है। इस नाम के पीछे भी उनकी एक दिलचस्प कहानी छिपी है। वे बताते हैं, ‘तबाही नाम थोड़ा अटपटा है, इसलिए सोचा कि अच्छे कामों में ही तबाही मचाई जाए।’ खास बात यह है कि नदी में सफाई के दौरान वे गंभीर रूप से बीमार भी पड़े, उनके हाथ-पैरों में त्वचा का गंभीर संक्रमण भी हुआ लेकिन इससे उनका हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर पैसे जुटाए और लगभग 30,000 खर्च कर सफाई के औजार खरीदे व कचरा हटाने के लिए जेसीबी मशीन भी लगवाई। बिट्टू को हाल ही में सीएम मोहन यादव ने भी सम्मानित किया है। जब अजनार



नदी की सफाई में बिट्टू जुटा, तब लोगों ने उसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। हालांकि, इसी के बीच 30 मार्च को उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने बिट्टू का वीडियो शेयर किया। उसमें उन्होंने आलोचना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर लाइक्स पाने की चाहत में किसी अच्छे काम का जরিफ बन सकती है, तो इसमें कोई

आपत्ति नहीं है। इस दौरान उन्होंने बिट्टू को अपना आदर्श भी बताया। इधर, केविन पीटरसन ने इंस्टाग्राम पर बिट्टू की पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि मैंने आज सुबह यह कहानी पढ़ी और सोचा कि इसे आपके साथ साझा करना चाहिए शाबाश, भाई! 20 साल की उम्र में बिट्टू तबाही एक प्रदूषित नदी में उतर गए। न हाथों में दस्ताने थे, न

पैरों में जूते और न ही उन्हें तेरना आता था। फिर भी उन्होंने अकेले ही नदी की सफाई शुरू कर दी। 26 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के ब्यावरा में एक मॉडल के पास बीएससी के छात्र बिट्टू ने अजनार नदी की सफाई का अभियान शुरू किया। नदी के कुछ हिस्से कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। बिट्टू ने वहां से प्लास्टिक और अन्य कचरा निकालना शुरू किया। उन्होंने पूजा सामग्री से निकलने वाले कचरे को खाद में बदलने की पहल भी की और दोस्तों के साथ मिलकर पैसे जुटाकर सफाई के औजार और कूड़ेदान खरीदे। इस अभियान पर करीब 30 हजार रुपये खर्च हुए। एक समय तो उनके हाथों में संक्रमण भी हो गया, लेकिन उन्होंने सफाई के काम नहीं छोड़ा। इसके बाद उनकी मुहिम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर हजारों लोगों तक पहुंचे। कुछ लोगों ने

उन पर लाइक्स और लोकप्रियता के लिए यह सब करने का आरोप भी लगाया। बिट्टू के उपनाम ‘तबाही’ का अर्थ विनाश होता है। लेकिन आज वह किसी और चीज की तबाही के लिए जुटे हैं- जल प्रदूषण के विनाश के लिए। क्योंकि कई बार बदलाव की शुरुआत तब होती है, जब कोई एक व्यक्ति दूसरों का इंतजार करना छोड़कर खुद पहला कदम उठा लेता है। मेरी नजर में बिट्टू एक असली हीरो हैं। वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान के कदवार हैं! सीएम डॉ मोहन यादव ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि बिट्टू ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प से सिर्फ अजनार नदी की सफाई ही नहीं की, बल्कि अपने प्रयासों से समाज को यह संदेश भी दिया है कि बदलाव के लिए बड़ी भीड़ नहीं, एक सच्ची पहल ही काफी है।



बिट्टू तबाही से मिले मुख्यमंत्री

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर का रहने वाला बिट्टू तबाही एक बार फिर चर्चा में है। शुक्रवार को वह दिनभर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। ट्रेंड होने के बाद उसे मुख्यमंत्री ने भी शुक्रवार को मिलने बुलाया। सीएम से बिट्टू तबाही की मुलाक़ात के बाद ब्यावरा नगर पालिका ने रविवार सुबह अजनार नदी को सफाई को लेकर अभियान शुरू कर दिया है।असल में सोशल मीडिया पर नदी की सफाई को लेकर उसके द्वारा उल्टी गई तस्वीर को किसी ने एआई फ़िल्टरड लिख दिया। इसके बाद बिट्टू ने सभी को आईना दिखा दिया। उसकी मेहनत और उसके द्वारा किए गए काम के बाद की तस्वीरें बताईं हैं। देश के बाव ही विदेशों में भी उसके वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और ख़ूब तारीफें वह बतोर रख है। बिट्टू के जच्चे को देखकर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मिलने का न्यौता मिला। शुक्रवार को बिट्टू मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचा। देर शाम हुई मुलाक़ात में सीएम यादव ने बिट्टू के काम की सराहना की है। साथ ही हर संभव मदद देने की बात कही है। साथ ही कहा कि बिट्टू की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बिट्टू तबाही से मुलाक़ात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। शुक्रवार को सीएम मोहन यादव और बिट्टू तबाही की मुलाक़ात के बाद रविवार सुबह ब्यावरा नगर पालिका हरकत में आया। नगर पालिका ने बिट्टू तबाही के सफाई अभियान का समर्थन करते हुए अजनार नदी में जमा पुराने कचरे और पॉलीथीन को जेसीबी और पोकलेन मशीन के माध्यम से साफ किया।

क्रिकेटरों के लिए अलग होटल की व्यवस्था नहीं बीसीसीआई अपनी पसंद का होटल ले सकता है

टोक्यो। जापान में होने वाले एशियन गेम्स के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भारतीय ओलंपिक संघ अलग से होटल की व्यवस्था नहीं करेगा। अगर बीसीसीआई आयोजकों की ओर से तय होटलों के बजाय अपनी पसंद का होटल चुनता है, तो खिलाड़ियों के ठहरने, खाने, स्थानीय परिवहन और मैच वेन्यू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बोर्ड की होगी। आईओए के सीईओ रघुराम अय्यर ने कहा कि एशियन गेम्स में शामिल सभी 36 खेलों के खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। बीसीसीआई सीईओ हेमांग अमीन और आईओई सीईओ रघुराम अय्यर के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। बीसीसीआई अगले हफ्ते की शुरुआत में एक एडवॉंस्ड टीम जापान भेजेगा।यह टीम होटल, क्रिकेट वेन्यू और दूसरी स्थानीय सुविधाओं का जायजा लेगी। इसके बाद बोर्ड तय करेगा कि आयोजकों की ओर से दिए गए होटलों में रहना है या अपनी व्यवस्था करनी है। अय्यर ने कहा कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों के हित में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर बोर्ड अलग व्यवस्था करता है तो आईओए को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी बीसीसीआई की होगी।

मैंस टीम के लिए श्री स्टार, वूमंस को 4-स्टार होटल

एशियन गेम्स के आयोजकों ने भारतीय



मैंस टीम के लिए श्री स्टार होटल नागोया एकिमाए और वूमंस टीम के लिए 4-स्टार ग्रैंड होटल की व्यवस्था की है। दोनों होटलों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेटरों के आमतौर पर रहने वाले फाइव स्टार होटल की तुलना में ये एक लेवल नीचे हैं। खिलाड़ियों के लिए कमरे ट्विन-शेयरिंग के आधार पर दिए जाएंगे।

यही व्यवस्था बीसीसीआई के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

अलग होटल में भी लागू रहेंगे सुरक्षा और डोपिंग नियम

अगर बीसीसीआई अपनी व्यवस्था करता है तो क्रिकेट एशियन गेम्स सिस्टम से बाहर नहीं होंगे। खिलाड़ियों पर गेम्स के

सुरक्षा, एंक्वेटेशन और एक्सेस प्रोटोकॉल लागू रहेंगे। बिना वैध एंक्वेटेशन वाले बाहरी लोगों को खिलाड़ियों के होटल में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा वाड़ा और इंटरनेशनल टैस्टिंग एजेंसी के डोप-कंट्रोल अधिकारियों को खिलाड़ियों के ठिकाने की जानकारी देनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर रैंडम डोप टेस्ट किया जा सके।

अयूब-किऑंग की जोड़ी को हराकर सात्विक-चिराग चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे



शेनझेन (चीन)। भारत के सात्विकसराज रंकीरेड्डी और चिराग शेठ्टी जोड़ी ने भी टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मलेशिया के नूर मोहम्मद अजीरन अयूब और टैन वी किऑंग की जोड़ी के खिलाफ जीत दर्ज कर चाइना मास्टर्स के पुरुष युगल बैडमिंटन में जगह बना ली है। आज यहां खेले गये सेमीफाइनल में बैडमिंटन रैंकिंग में पांचवें पायदान पर मौजूद भारत की सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर मोहम्मद अजीरन अयूब और टैन वी किऑंग की जोड़ी को एक घंटे छह मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 18-21, 21-11 से हराकर चाइना मास्टर्स के फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ सात्विक और चिराग पिछले चार संस्करणों में तीसरी बार चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे हैं। वे

2023 और 2025 में रनर-अप रहे थे और 2024 में सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। एशियाई खेलों के मौजूदा पुरुष युगल बैडमिंटन चैंपियन के पास अब अपना पहला चाइना मास्टर्स खिताब जीतने का एक और मौका होगा। 2005 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट को अब तक किसी भी भारतीय शटलर ने नहीं जीता है। मलेशियाई जोड़ी ने शुरुआती गेम में 5-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन सात्विक और चिराग ने लगातार सात अंक जीतकर वापसी की और मिड-गेम इंटरवल तक 11-9 की बढ़त बना ली। ब्रेक के बाद भी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपनी बढ़त बनाए रखी और 17-15 के स्कोर से आगे बढ़ते हुए अगले पांच में से चार अंक जीतकर पहला गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में भी मलेशियाई खिलाड़ियों ने तेज़ शुरुआत की और 4-0 की

बढ़त बना ली, लेकिन फिर सात्विक और चिराग ने अपनी लय हासिल की और 10-8 से आगे हो गए। इसके बाद बढ़त कई बार बदली और दोनों जोड़ियां 18-18 के स्कोर पर बराबरी पर आ गईं। हालांकि, नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी किऑंग ने लगातार तीन अंक जीतकर मैच को निर्णायक गेम (डिसाइडर) तक पहुंचा दिया। सात्विक और चिराग ने यह सुनिश्चित किया कि निर्णायक गेम में मलेशियाई खिलाड़ियों की तेज़ शुरुआत वाली रणनीति दोबारा न चल पाए। उन्होंने शुरुआत से ही नियंत्रण बनाए रखा और मिड-गेम इंटरवल तक 11-4 की बढ़त हासिल कर ली। साइड बदलने के बाद भी भारतीय जोड़ी ने खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा और निर्णायक गेम जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

सच बाजार

ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के पास 98,000 करोड़ रुपये का स्टॉक फंसा, जानें रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा

एजेंसी ॥ नई दिल्ली

भारतीय ऑटो कंपोनेंट उद्योग में करीब 98,000 करोड़ रुपये का स्टॉक फंसा हुआ है। इसमें से 29,000 से 39,000 करोड़ रुपये तक की राशि स्टॉक प्रबंधन में सुधार करके जारी की जा सकती है। यह राशि कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग हो सकती है। एमएसएमई क्षेत्र को इससे 4,000 से 5,600 करोड़ रुपये का लाभ मिल सकता है। वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है।

रिपोर्ट बताती है कि देश के 80 फीसदी ऑटो कंपोनेंट निर्माता एमएसएमई हैं। खपत-आधारित इस्तेमाल का तरीका अपनाने वाली कंपनियां 30 से 40 फीसदी तक स्टॉक कम कर सकती हैं। भारत के ऑटो कंपोनेंट एमएसएमई का कुल राजस्व लगभग 2.4 से 2.9 लाख करोड़ रुपये है। उत्पादकता में 30 फीसदी सुधार से 74,000 से 88,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक

राजस्व मिल सकता है। सामग्री लागत के बाद, यह 29,000 से 44,000 करोड़ रुपये का वृद्धिशील मूल्य पूल बना सकता है। इन लाभों से एक आत्म-सुदृढ़ निवेश चक्र बन सकता है। परिचालन सुधारों से कार्यशील पूंजी मुक्त होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। इससे बाहरी पूंजी तक पहुंच भी बेहतर होगी।

क्या एमएसएमई भविष्य के लिए तैयार नहीं हैं?

वेक्टर के अध्ययन से पता चला कि 95 फीसदी उद्योग नेता मानते हैं कि एमएसएमई भविष्य की वृद्धि के लिए पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे। यह अध्ययन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) के 66वें वार्षिक सत्र में जारी किया गया था। शोध में भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक क्षमताओं और वर्तमान में उपलब्ध क्षमताओं के बीच बड़ा अंतर पाया गया। यह अंतर ऑटोमोटिव एमएसएमई

आपूर्तिकर्ताओं और टियर-1, टियर-2 कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के इनपुट पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए जुलाई से अगस्त 2026 तक 21 वरिष्ठ उद्योग अधिकारियों से डेटा एकत्र किया गया था।

क्या विनिर्माण क्षमता को बरकरार रखना है चुनौती?

अध्ययन में क्षमता का विरोधाभास भी सामने आया है। संयंत्र औसतन 75 से 85 फीसदी क्षमता उपयोग पर चल रहे हैं। फिर भी, 91 फीसदी उत्तरदाताओं ने क्षमता को एक बड़ी चुनौती माना। बार-बार होने वाले बदलाव, गुणवत्ता में हानि और पुनः कार्य तथा खराब सामग्री प्रवाह प्रभावी उत्पादक क्षमता को कम करते हैं। वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप के मैनेजिंग पार्टनर रविंद्र पटेल की ने कहा, अक्सर केवल अधिक क्षमता जोड़ने का नहीं है। उन्होंने कहा, भारतीय कंपनियों के पास जो क्षमता है, उसका एक बड़ा

हिस्सा उत्पादक उत्पादन में नहीं बदल रहा है।

भारत के लिए आगे क्या है महत्वपूर्ण?

रविंद्र पटेल की अनुसार, परिचालन में फंसी नकदी को मुक्त करना महत्वपूर्ण है। मौजूदा कारोबार की अर्थव्यवस्था में सुधार करना और अधिशेष को क्षमताओं में लगाना जरूरी है। यह तय करेगा कि भारतीय आपूर्तिकर्ता भविष्य की ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में कैसे बढ़ेंगे। रिपोर्ट कहती है कि भारत के ऑटोमोटिव आपूर्तिकर्ता आधार की मजबूत करना उद्योग की प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण है। वाहन का मूल्य बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। भारत की घरेलू स्थानीयकरण और वैश्विक सोर्सिंग की अगली लहर पर कब्जा करने की क्षमता आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करेगी।

प्याज के दाम ने बिगाड़ा रसोई का बजट 25 से बढ़कर 60 रुपए किलो पहुंचा भाव

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में प्याज की कीमतों में एक बार फिर तेजी आ गई है। महज कुछ दिनों में प्याज का भाव 25 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 60 रुपए तक पहुंच गया है। इससे रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। लोगों का कहना है कि बरसात शुरू होने से पहले ही सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बारिश के दौरान महंगाई किस कदर परेशान करेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। थोक व्यापारियों के अनुसार मंडी में प्याज की आवक तेजी से कम हुई है। सामान्य दिनों में प्रतिदिन 15 से 20 ट्रक प्याज पहुंचते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर महज 4 से 5 ट्रक रह गई है। मौजूदा समय में राजस्थान, नासिक और इंदौर से सीमित मात्रा में प्याज मंडी पहुंच रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सबसे अधिक असर मध्य प्रदेश में बारिश के कारण प्याज की फसल



खराब होने से पड़ा है। फसल की खुदाई के बाद हुई बारिश के चलते बड़ी मात्रा में प्याज खेतों में ही सड़ गया। इसके अलावा नासिक और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से आवक प्रभावित हुई है। थोक व्यापारियों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में प्याज की कीमतों में करीब 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे मांग और आपूर्ति में अंतर के अलावा पिछली रबी फसल में उत्पादन कम होना भी प्रमुख कारण है।

व्यापारियों के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटाना भी कीमत बढ़ने की एक वजह माना जा रहा है। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिसंबर 2023 में लगाए गए निर्यात प्रतिबंध को वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत में हटा दिया था। आवक में कमी और बढ़ती मांग के चलते आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों पर दबाव बने रहने की आशंका है।

रिकॉर्ड स्तर पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार: 740.8 अरब डॉलर पर पहुंचा आंकड़ा, जानें इजाफे का क्या है कारण

एजेंसी ॥ नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 11.475 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 740.803 अरब अमेरिकी डॉलर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि है। पिछले रिकॉर्डिंग सप्ताह में भी यह भंडार 12.422 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 729.328 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था। यह लगातार दूसरे सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है।इससे पहले, विदेशी मुद्रा भंडार का सर्वकालिक उच्च स्तर 27 फरवरी को 728.494 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह मध्य पूर्व संघर्ष के ठीक पहले हासिल किया गया था। भू-राजनीतिक तनावों के कारण रुपये में गिरावट आई थी। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक को डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप कई हफ्तों तक भंडार में गिरावट

देखी गई थी। इस साल जून में भारतीय रिजर्व बैंक ने रियायती विदेशी मुद्रा अदला-बदली पहल की घोषणा की थी। यह स्थानीय मुद्रा के तेज मूल्यह्रास के बीच की गई थी। इस पहल से 132 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नया प्रवाह हुआ है।

विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि क्यों हुई?

भारतीय रिजर्व बैंक की रियायती विदेशी मुद्रा अदला-बदली पहल (एससीएनआर-बी) इस वृद्धि का मुख्य कारण है। इस साल जून में स्थानीय मुद्रा के मूल्यह्रास को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। इस पहल के कारण देश में 132 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नया पूंजी प्रवाह आया है। इसने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पहल वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है।

भंडार के प्रमुख घटक क्या हैं?

28 अगस्त को समाप्त सप्ताह

के लिए केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भंडार का एक प्रमुख घटक हैं। ये 9.337 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 600.67 अरब अमेरिकी डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त की गई इन परिसंपत्तियों में गैर-अमेरिकी इकाइयों जैसे यूरो, पाउंड और येन के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव शामिल है। स्वर्ण भंडार का मूल्य भी इस सप्ताह 2.191 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 116.409 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। यह वृद्धि भारत की आर्थिक मजबूती का संकेत देती है।

अन्य घटकों की स्थिति क्या है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) घटक दस लाख अमेरिकी डॉलर बढ़कर 18.81 अरब अमेरिकी डॉलर हो गए। रिपोर्टिंग सप्ताह के अंत में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ भारत की आरक्षित स्थिति भी 11 दस लाख अमेरिकी डॉलर घटकर 4.914 अरब अमेरिकी डॉलर रह गई।

भारत आ रहा है इस देश का बड़ा बिजनेस डेलिगेशन, अरबों डॉलर की ट्रेड डील पर होगी बात

एजेंसी ॥ नई दिल्ली

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दक्षिण अफ्रीका का एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते भारत के दौर पर आ रहा है। यह प्रतिनिधिमंडल 10 और 11 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम की बैठकों में हिस्सा लेगा। यह महत्वपूर्ण दौर आगामी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार अंतर्सुलन को दूर करना और नए निवेश अवसरों की तलाश करना है।इस दौर का नेतृत्व साउथ अफ्रीकन ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की चेयरपर्सन बुसी माबुजा कर रही हैं। वर्तमान में दोनों

देशों के बीच बड़ा व्यापार अंतर है। साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका को भारत के साथ व्यापार में लगभग 3।18 अरब डॉलर का व्यापार घाटा उठाना पड़ा था।फिलहाल, दक्षिण अफ्रीका से भारत को मुख्य रूप से कोयला, मैंगनीज और केमिकल वुड पल्प जैसी कच्ची रॉ मैटेरियल का निर्यात किया जाता है। वहीं, भारत से दक्षिण अफ्रीका को पेट्रोलियम उत्पाद, गाड़ियां, दवाइयां और मशीनरी भेजी जाती है। दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल इस बार पारंपरिक च्छेता-विक्रेताज मॉडल को बदलकर सह-निवेश और तकनीकी सहयोग पर जोर देगा, ताकि वे भारत को ऊंचे मूल्य वाले औद्योगिक उत्पादों का निर्यात कर सकें।

इन प्रमुख क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

दोनों देशों के बीच होने वाली बैठकों

में कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर चर्चा की जाएगी

ऑटोमोटिव हब: भारतीय तकनीक और पूंजी का उपयोग करके दक्षिण अफ्रीका को एक क्षेत्रीय ऑटोमोटिव उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करना।

फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य: दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में साझेदारी करना, ताकि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ सके।

अत्याधुनिक तकनीक और कौशल विकास: प्रौद्योगिकी,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में स्किल-एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करना।

हरित ऊर्जा: रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम स्थापित करना।

कृषि और पैकेजिंग: भारतीय बाजार में दक्षिण अफ्रीकी कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना और भारत की आधुनिक फूड प्रोसेसिंग व पैकेजिंग तकनीक को अपनाना।

अफ्रीकी मुक्त व्यापार और ब्रिक्स बैंक की भूमिका

एसएबीबीसी की चेयरपर्सन बुसी माबुजा के अनुसार, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र भारतीय कंपनियों के लिए पूरे अफ्रीका के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश करने का एक शानदार अवसर है। इसके अलावा, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दक्षिण अफ्रीका में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए 6.41 अरब डॉलर से अधिक की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।

टाटा के जेएलआर में छंटनी की खबर: ब्रिटेन में जाएंगी 4,000 नौकरियां; क्या ट्रंप का टैरिफ और घटती बिक्री कारण?

नई दिल्ली। वैश्विक ऑटो सेक्टर में मंदी के बीच, टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली लक्जरी कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने एक बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स की एक रिपोर्ट

के अनुसार, कंपनी ब्रिटेन में अगले दो साल में करीब 4,000 नौकरियों को कटौती करने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जेएलआर का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए आयात शुल्कों (टैरिफ), घटती

बिक्री और बढ़ती उत्पादन लागत का नतीजा है। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार, जेएलआर पर इस समय लागत कम करने का भारी दबाव है। दरअसल, जून 2026 को समाप्त तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है

राजस्व में गिरावट: तिमाही के दौरान कंपनी का राजस्व करीब 10% घट गया। मुनाफे में भारी कमी: कंपनी का कर-पूर्व लाभ दो-तिहाई से अधिक गिरकर केवल 10.9 करोड़ पाउंड रह गया।

ब्रीफ न्यूज़

राहुल के कार्यक्रम में केवल युवाओं पर दांव

भोपाल। राहुल गांधी के 19 सितंबर को इंदौर में होने वाले ‘छात्रों की गुंज’ कार्यक्रम में कांग्रेस ने भीड़ जुटाने के बजाय युवा चेहरो पर फोकस करने की रणनीति बनाई है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि आयोजन में 30 वर्ष तक की उम्र के युवाओं का ही पंजीयन किया जाएगा। यानी इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और उम्रदराज कार्यकर्ताओं की भूमिका कम के सामने नहीं, बल्कि युवाओं को कार्यक्रम तक पहुंचाने तक सीमित रहगी। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने इंदौर को 32 जोन में बांटा है। इनमें 19 जोन शहरी और 13 ग्रामीण क्षेत्र में रखे गए हैं। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों को प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों तक जाकर युवाओं का पंजीयन कराने का टास्क दिया गया है। कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर संगठन के निचले स्तर तक लक्ष्य तय कर दिए हैं। प्रत्येक पदाधिकारी को दो-दो हजार पंजीयन कराने का टारगेट दिया गया है। पार्टी का जोर इस

छात्रों की गुंज: कांग्रेस ने बुजुर्ग नेताओं को किया साइडलाइन, 32 जोन में बांटकर कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल और कोचिंग तक पहुंचने की तैयारी

बात पर है कि आयोजन में आने वाली भीड़ पारंपरिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की न होकर युवा और छात्र होे। इसके लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को युवाओं के बीच सीधे जाने के बजाय संगठनात्मक मदद की जिम्मेदारी दी गई है। वार्ड और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को भी घर-घर संपर्क कर युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

कांग्रेस का नया प्रयोग : राहुल गांधी के ‘छात्रों की गुंज’ कार्यक्रम को कांग्रेस युवाओं के बीच शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर संवाद के रूप में पेश कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे पहले कोटा, प्रयागराज, देहरादून और पुणे में हुए आयोजनों में भी युवाओं को ही प्रवेश दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर हुई बैठक में एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और शहर व जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने तैयारियों पर चर्चा की। पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती तय उम्र सीमा के भीतर बड़ी संख्या में युवाओं को पंजीकृत कर कार्यक्रम में लाना है।

बुजुर्गों की गुंज नहीं : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी उम्र सीमा को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट कर दी है। उनका कहना है कि कार्यक्रम युवाओं और छात्रों के लिए है तथा राहुल गांधी शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर उनसे संवाद करेंगे। उन्होंने इसे गैर-राजनीतिक आयोजन बताया है। इस तरह इंदौर का यह आयोजन कांग्रेस के लिए सिर्फ राहुल गांधी की सभा नहीं, बल्कि युवा वोटों और छात्रों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। उम्र की 30 साल की सीमा ने इस आयोजन को सामान्य राजनीतिक कार्यक्रमों से अलग करवा कर दिया है, लेकिन अब अस्थली परीक्षा कांग्रेस के संगठन की है-क्या 32 जोन और हजारों पंजीयन के जरिए पार्टी राहुल गांधी के सामने वास्तविक युवा भागीदारी का बड़ा चेहरा खड़ा कर पाएगी?

अजाक्स भवन के मालिकाना हक को लेकर तकरार

मामला पहुंचा थाने, कोर्ट के आदेश पर बढ़ाई सुरक्षा

भोपाल। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) में भवन के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद अब खुत्कर सामने आ गया है और मामला थाने तक जा पहुंचा है। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अजाक्स भवन को खाली नहीं कराया जा रहा है। विवाद और सुरक्षागत खतरों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अजाक्स भवन के बाहर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अजाक्स के प्रतिनिधियों ने पुलिस थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और बताया कि भोपाल कोर्ट द्वारा इस मामले में सख्त रुख अपनाया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मुकेश मौर्य द्वारा अजाक्स भवन पर अवैध रूप से कब्जा जमाया गया है, जिससे संगठन के प्रशासनिक और सामाजिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। पदाधिकारियों के अनुसार, भोपाल कोर्ट ने इस मामले का संज्ञा लेते हुए मुकेश मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

विवाद बढ़ता देख अलर्ट पर पुलिस : अजाक्स के दोनों गुटों के बीच जारी इस खिंचाव और संभावित टकराव की स्थिति को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल अलर्ट मोड पर है। अप्रिय घटना से निपटने के लिए अजाक्स भवन के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मुख्य रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और अदालती निर्देशों के अनुरूप आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

मध्यप्रदेश में अब सड़क सफर होगा महंगा!

12 और सड़कों पर लगेगा टोल, सरकार का सालाना 3 हजार करोड़ कमाई का प्लान

भोपाल। मध्यप्रदेश में आने वाले समय में सड़क से सफर करना महंगा हो सकता है। राज्य सरकार सड़कों से होने वाली आय बढ़ाने के लिए टोल व्यवस्था का विस्तार करने की तैयारी में है। कम से कम 12 और सड़कों को टोल के दायरे में लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य सड़कों को भी भविष्य में इस व्यवस्था से जोड़ने की योजना है।
फिलहाल प्रदेश में मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) की अलग-अलग योजनाओं के तहत 93 सड़कों पर 139 टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं। विभाग का मानना है कि नई सड़कों को टोल व्यवस्था से जोड़कर सरकार की आय में बड़ा इजाफा किया जा सकता है।

अभी 400 करोड़, लक्ष्य 3 हजार करोड़ तक : पीडब्ल्यूडी से जुड़े अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के टोल से सालाना करीब 4 हजार करोड़ रुपये की आय होती है। इसके मुकाबले पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी की टोल से कमाई करीब 400 करोड़ रुपये सालाना है। इसी अंतर को देखते हुए विभाग अगले 10 से 15 साल में टोल से होने वाली आय को बढ़ाकर 2 हजार से 3 हजार करोड़ रुपये सालाना तक पहुंचाना चाहता है। इसके लिए नई सड़कों का निर्माण टोल आधारित मॉडल पर करने पर जोर दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार टोल

महानगर

मंत्रालय में नहीं लगी बायोमेट्रिक हाजिरी

सीएम के फरमान, तीन बार निर्देश, फिर भी तारीख तय नहीं

भोपाल
सरकारी दफ्तरों में समय पर पहुंचने और जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पिछले आठ महीने में तीन बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन व्यवस्था की शुरुआत उस मंत्रालय में ही नहीं हो पाई जहां से प्रदेश का प्रशासन चलता है। अप्रैल से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है, मशीनों और जरूरी सामग्री की खरीदी की प्रक्रिया भी शुरू हुई, लेकिन करीब पांच महीने गुजरने के बाद भी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू नहीं हो सकी। अब अधिकारियों का कहना है कि सिस्टम तैयार किया जा रहा है और करीब दो महीने में व्यवस्था शुरू हो सकती है। पहले चरण में मंत्रालय के साथ सतपुड़ा और विंध्याचल भवन को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पहली बार 7 जनवरी को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सरकारी कार्यालयों का काम सुबह 10 बजे से शुरू करने और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी



सामग्री की खरीदी के लिए एमपीएसआईडीसी को वर्क ऑर्डर जारी करने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन खरीदी और सिस्टम तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। अधिकारियों के मुताबिक एमपीएसईडीसी सिस्टम तैयार कर रहा है और अब लगभग दो महीने में इसे शुरू किया जा सकता है। यानी जिस व्यवस्था को अप्रैल में शुरू करने की तैयारी थी, उसके लिए अब आगे भी करीब दो महीने का इंतजार करना पड़ सकता है।

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

पहले रजिस्टर, फिर फेस अटेंडेंस... दोनों बेअसर : मंत्रालय में कर्मचारियों की लेटलतीफी रोकने के लिए यह पहला प्रयोग नहीं है। इससे पहले भी दो व्यवस्थाएं लागू की जा चुकी हैं। जून 2024 में अटेंडेंस रजिस्टर में कर्मचारियों के हस्ताक्षर की व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके बाद फरवरी 2025 में आधार बेस्ड फेस अटेंडेंस लागू की गई। लेकिन खबर के मुताबिक दोनों व्यवस्थाएं कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने की समस्या पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा सकीं। अब तीसरी बार बायोमेट्रिक व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी की उपस्थिति सीधे दर्ज होगी और हाजिरी में पारदर्शिता आएगी।

फाइव-डे वीक के बीच समय की पाबंदी बढ़ा मुद्दा : प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में वर्ष 2021 से फाइव-डे वीक लागू है। 8 अप्रैल 2021 के आदेश के बाद कार्यालयों का समय सुबह 10 से शाम 6 बजे किया गया था। रविवार के साथ शनिवार को भी अवकाश रहने लगा। ऐसे

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी

बायोमेट्रिक हाजिरी करने वाले कर्मचारी